खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

934. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के बेकार प्रदर्शन को देखते हुए सरकार उन्हे भारत या विदेश में जो गहन प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) खेलों के स्तर में सुधार लाने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी स्तरों में उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिये भारत सरकार ने विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखायें जारी की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एशियाई खेल, 1990 में हमारी टीमों की तैयारी के लिये पता लगाये गये प्रत्येक प्राथमिकता खेल विषयों से संबंधित दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम की तैयारी अपेक्षित है । सभी प्राथमिकता खेल विषयों के बारे में दीर्घकालीन विकास योजना अब तैयार की गई है, उस पर चर्चा की गई है और यह स्वीकृत की गई है । इन दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों के अनुसार खिलाड़ियों का प्रशिक्षण चल रहा है ।

1987–88 में विभिन्न खेल विषयों में निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार कुल 65 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये थे :—

1. एथलेटिक्स	8
2. बैडमिन्टन	5
3. मुक्केबाजी	6
4. घुड़सवारी	—
5. हाकी (पुरुष)	5
6. हाकी (महिला)	5
7. जूडो	2
8. निशानेबाजी	3
9. तैराकी	3
10. बालीबाल	6
11. भारोत्तोलन	11
12. कुश्ती	7
13. नौकायन	2
14. तीरंदाजी	2
15. पाल नौकायन	—
	65

प्रशिक्षण योजना के एक भाग के रूप में टीमों/खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये विदेश भेजा गया था । कुछ खेल विषयों के लिये विदेशी प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है ।

अपेक्षित उपस्करों की भी व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

राजस्थान में रेल यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राशि

935. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेल यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) राजस्थान में चालू योजना के अधीन पूरी की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजस्थान में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Malpractices in the Manufacture and marketing of Drugs

936. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have examined the working of the provisions of Drugs and Cosmetics Act, dealing with the manufacture and marketing of spurious drugs, the medicine licensing system and also the effectiveness or otherwise of the various agencies/authorities responsible for the inspection/testing of the manufactured drugs in view of the recent killer drug tragedy in Tata Memorial Hospital and earlier deaths due to adulterated drugs in Bombay's J. J. Group of Hospitals and in other hospitals in various parts of the country, so as to ensure maintenance of standard quality and to check malpractices; and

(b) if so, what has been the outcome thereof, stating the steps contemplated by Government to make the law more stringent and to plug the loopholes, if any, in the working of various agencies, to make them effective instruments in the production and marketing of quality drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) The enforcement of Drugs and Cosmetics Act is the responsibility of State Governments. A statutory body viz. Drugs Consultative Committee having representatives of all the State Governments and the Central Governments advises the Central Government and all the State Governments on matters relating to uniform administration of the provisions of the Drugs and Cosmetics Act.

The Act was amended in 1982 giving a separate definition of spurious drugs. The maximum punishment was enhanced to life imprisonment in cases of drugs which on use were likely to cause death or grievous hurt. The Drugs and Cosmetics Act was also amended in 1986 empowering a purchaser of a drug or cosmetic to enable to get a sample of a drug tested and to launch prosecution for violations of provisions of Drugs and Cosmetics Act and Rules.

Workshop on the Status of widows and destitute women in India

937. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a three day workshop was held in Delhi in April, 1988 on 'Status of Widows and destitute women in India'; and

(b) if so, what are the recommendations of the workshop and Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached herewith (*See* below). As for Government's reaction, the detailed report of the workshop is awaited

Statement

1. That a thorough inquiry should be instituted by the Central Government into the "poor state of affairs prevailing in the widows" Ashrams in the country, especially at Brindavan, Varanasi and Puri.

2. As majority of the widows at Banaras and Mathura are from Bengal, we urge the West Bengal government to take effective steps to prevent forced migration of the destitute women and widows to the holy places for refuge.